

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति
प्रेस कॉन्फ्रेंस का संपादित प्रतिलेख: 05 अगस्त, 2022

आरबीआई से प्रतिभागी:

श्री शक्तिकांत दास - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री एम. के. जैन - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. माइकल डी. पात्रा - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री एम. राजेश्वर राव - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री टी. रबी शंकर - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. ओ. पी. मल्ल - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. राजीव रंजन - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
संचालक: श्री योगेश दयाल - मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

नमस्कार और इस मौद्रिक नीति के घोषित होने के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं: गवर्नर श्री शक्तिकांत दास; उप गवर्नर्स, श्री एम. के. जैन, डॉ. माइकल डी. पात्रा, श्री एम. राजेश्वर राव, और श्री टी. रबी शंकर; और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो कार्यपालक निदेशक, डॉ. ओ. पी. मल्ल और डॉ. राजीव रंजन।

सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कुछ शुरुआती संबोधन दें और उसके बाद हम प्रश्न-उत्तर सत्र शुरू कर सकते हैं।

शक्तिकांत दास:

सुप्रभात। आपकी भागीदारी के लिए धन्यवाद।

यह वक्तव्य, मौद्रिक नीति प्रस्ताव और अन्य सभी घोषणाएं पहले से ही आपके पास हैं और मुझे यकीन है कि आपने उन्हें पढ़ लिया होगा। अब मौद्रिक नीति और अन्य निर्णयों से जो व्यापक तस्वीर उभरकर सामने आ रही है, जिनकी घोषणा हमने आज की है, मैं उन्हें छह बिंदुओं के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूंगा।

1) पहला, अत्यधिक उथल-पुथल और अनिश्चितता के सागर में, भारतीय अर्थव्यवस्था समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता का एक द्वीप है। आर्थिक विकास मजबूत और लचीला है। अब ये सभी—यानी वित्तीय स्थिरता, समष्टि-आर्थिक स्थिरता, और विकास का लचीलापन—दो 'ब्लैक स्वान' घटनाओं (अत्यंत अप्रत्याशित घटनाओं) के एक के बाद एक घटने और कई झटकों के बावजूद संभव हो पाए हैं। हमने जो कुछ भी कहा है, उससे निकलने वाला यह पहला मुख्य निष्कर्ष है।

2) दूसरा, इस समय ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सीपीआई महंगाई अपने चरम पर पहुँच चुकी है, और उम्मीद है कि इस साल की चौथी तिमाही और अगले साल की पहली तिमाही में इसमें नरमी आएगी। हमने एमपीसी के बयान और प्रस्ताव में भी इस बात का ज़िक्र किया है। लेकिन महंगाई अभी भी अस्वीकार्य रूप से ऊँचे स्तर पर बनी हुई है, और कई ऐसी अनिश्चितताएँ भी हैं जो भविष्य के परिदृश्य को धुंधला कर रही हैं। इसलिए, मौद्रिक नीति को कदम उठाना होगा, और यही वजह है कि आज मौद्रिक नीति के तहत दरों में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी की घोषणा की गई; यह एमपीसी का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव था।

3) तीसरा बिंदु यह है कि अगर आप पहले दो बिंदुओं को एक साथ देखें, तो यह बात उभरकर सामने आती है कि महंगाई और महंगाई की उम्मीदों को काबू में रखने के लिए कदम उठाने ज़रूरी हैं। दूसरी बात जो सामने आती है, वह यह है कि मज़बूत आर्थिक गतिविधियाँ हमें कदम उठाने का अवसर देती हैं। विकास के पहलू को हमेशा ध्यान में रखा जाता है और एमपीसी की चर्चाओं के साथ-साथ एमपीसी के फ़ैसलों में भी इसे हमेशा शामिल किया जाता है।

4) चौथा बिंदु, जिसे मैं व्यापक परिदृश्य के हिस्से के तौर पर बताना चाहूँगा, वह यह है कि हमारे पास जो अतिरिक्त चलनिधि थी, उसे धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। मैंने अपने प्रस्ताव में इसका उल्लेख किया है। हमने यह भी कहा है कि बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर चलनिधि के संबंध में दो-तरफ़ा 'फ़ाइन-ट्यूनिंग' (बारीक समायोजन) के ऑपरेशन किए जाएँगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम में पर्याप्त चलनिधि बनी रहे।

5) पाँचवाँ बिंदु यह है कि बाहरी क्षेत्र के संबंध में, चालू खाता घाटा प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर रहने की उम्मीद है। हमारे आकलन के अनुसार, रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता घाटे की भरपाई करने की क्षमता मौजूद है। विदेशी मुद्रा भंडार मज़बूत बना हुआ है, और रिज़र्व बैंक विनिमय दर में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ाव से प्रभावी ढंग से निपटेगा; जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था, हमारा सुरक्षा कवच (अम्ब्रेला) मज़बूत बना हुआ है।

6) छठा और अंतिम बिंदु यह है कि मौद्रिक नीति को महंगाई और आर्थिक गतिविधियों की बदलती हुई गतिशीलता के आधार पर सोच-समझकर, नपे-तुले ढंग से और फुर्ती के साथ संचालित किया जाएगा। हमारा मुख्य ज़ोर अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षित और सुचारु 'सॉफ्ट लैंडिंग' सुनिश्चित करने पर बना रहेगा। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य के हिस्से के तौर पर भी कहा था, आरबीआई के लिए यह एक बार फिर वही दृष्टिकोण है, जिसे वह इस तीसरे वर्ष में भी अपना रहा है। हमने इसे महामारी के पहले साल में, दूसरे साल में और अब भी - जिन चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना हम कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए - अनुभव किया है।

तो, बस इतना ही मैं कहना चाहता था, अब मैं योगेश से कहूँगा कि वे हमें आगे ले जाएं।

योगेश दयाल:

धन्यवाद सर, शुरुआती संबोधन के लिए। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से श्री मयूर शेटी को अपना सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करूंगा।

मयूर शेटी, टाइम्स ऑफ इंडिया:

गवर्नर साहब, दरों में बढ़ोतरी बहुत तेज़ रही है और ये बहुत कम समय के अंतराल पर हुई हैं। क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि इससे मांग खत्म हो जाएगी? खासकर यह देखते हुए कि रेपो दर से जुड़ाव के कारण, आवास ऋण जैसे क्षेत्रों में भी ये बढ़ोतरी तुरंत लागू हो रही है। और दूसरा हिस्सा, आपकी इस दर में बढ़ोतरी तब भी हुई है जब आपने यह कहा था कि महंगाई शायद अपने चरम पर पहुंच चुकी है और हमने वस्तुओं की कीमतों में गिरावट भी देखी है। तो, आपकी यह कार्रवाई बाहरी मोर्चे से किस हद तक जुड़ी हुई है?

शक्तिकांत दास:

महंगाई सात प्रतिशत पर बनी हुई है, यानी, यह अस्वीकार्य रूप से ऊंचे स्तर पर है। हमारे अनुमानों के अनुसार भी, यह चालू वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में छह प्रतिशत से ऊपर बनी रहेगी; चौथी तिमाही का अनुमान 5.8 प्रतिशत है। महंगाई के इस तरह के रुख को देखते हुए, जाहिर है, मौद्रिक नीति को कार्रवाई करनी ही होगी।

रेपो दर को लेकर हमने जो कदम उठाए हैं, अगर आप उन्हें तुलनात्मक नज़रिए से देखें - हालांकि हमारे निर्णय मुख्य रूप से हमारे घरेलू कारकों से ही तय होते हैं - तो आप पाएंगे कि अगर आप दूसरे केंद्रीय बैंकों को देखें, तो आज 50 आधार अंक की बढ़ोतरी एक 'नया सामान्य' बन गया है। कई केंद्रीय बैंक अब 75 से 100 आधार अंक की बढ़ोतरी कर रहे हैं। एक रुझान यह भी दिख रहा है कि शायद 75 से 100 आधार अंक की दर बढ़ोतरी, 50 आधार अंक की बढ़ोतरी की जगह ले लेगी। रिज़र्व बैंक में, हम बहुत ही नपे-तुले और सोच-समझकर फैसले लेते हैं; हम दर में बदलाव का विकास पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखते हैं। इसलिए, विकास के पहलू को, और दर में बढ़ोतरी का हमारी मांग - यानी कुल मिलाकर उपभोक्ता मांग, तथा शहरी और ग्रामीण मांग - पर पड़ने वाले असर को भी हमने अपने आकलन में शामिल किया है। इसी आधार पर, और मौजूदा तथा अनुमानित महंगाई और विकास के समीकरणों को देखते हुए हमने एक संतुलित फैसला लिया है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब, मैं फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस की सुश्री श्रीतमा बोस की ओर रुख करूंगा।

सुश्री श्रीतमा बोस, फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस

धन्यवाद सर। मेरा पहला प्रश्न चलनिधि की स्थिति पर है, जो अब बहुत ज़्यादा अस्थिर होती जा रही है। चूंकि पिछली दरों में बढ़ोतरी का असर अभी तक जमा पर पूरी तरह से नहीं पड़ा

है, तो आपको क्या लगता है कि आगे चलकर यह स्थिति कैसे बदलेगी, जब हम आमतौर पर ज्यादा अस्थिर चलनिधि स्थितियों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं? सर, आज आपने जो महंगाई का अनुमान बताया है, क्या उसमें पिछली दो दरों में बढ़ोतरी के असर को भी शामिल किया गया है?

शक्तिकांत दास:

उन्हें शामिल किया गया है, लेकिन मैं उप गवर्नर माइकल पात्रा से अनुरोध करूंगा कि वे इस सवाल के दोनों हिस्सों का जवाब दें।

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

एक बार जब दरों पर कोई कार्रवाई हो जाती है, तो वह एक तथ्य बन जाता है। हम अपने अनुमान लगाने के लिए सभी तथ्यों का उपयोग करते हैं। यदि हम भविष्य की संभावित कार्रवाइयों को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो यह एक बेसलाइन परिदृश्य होता है, लेकिन बेसलाइन परिदृश्य में हमारे द्वारा पहले की गई कार्रवाई का तथ्य शामिल होता है।

जहां तक चलनिधि की स्थिति का सवाल है, आपने देखा होगा कि जमा जुटाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है, जिसकी शुरुआत थोक जमा से हुई है। हमें उम्मीद है कि जमा जुटाने की गति बहुत जल्द क्रेडिट (ऋण) की गति के बराबर हो जाएगी।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं इकोनॉमिक टाइम्स के श्री गोवर्धन रंगन की ओर रुख करूंगा।

एम. गोवर्धन रंगन, इकोनॉमिक टाइम्स:

लंबे समय से, नीति का उद्देश्य आर्थिक चलनिधि को एक टिकाऊ स्थिति में लाना था। अब यदि आप क्रेडिट-जमा अनुपात को देखें, तो यह वृद्धिशील क्रेडिट-जमा का 110 प्रतिशत है और क्रेडिट 14.0 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। बाहरी मांग भी बहुत मजबूत है और सीएडी (चालू खाता घाटा) लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है। इन सभी का सिस्टम में चलनिधि पर असर पड़ेगा। तो, चलनिधि के मामले में आरबीआई की क्या प्रतिक्रिया होगी, जब एक तरफ मजबूत आर्थिक सुधार हो रहा है और दूसरी तरफ एक तरह का भारी चालू खाता घाटा भी मौजूद है?

शक्तिकांत दास:

सबसे ज्यादा संभावना यही है कि दर में बढ़ोतरी का असर बैंक डिपॉजिट दर पर भी पड़ेगा। यह ट्रेंड पहले ही शुरू हो चुका है, और पिछले कुछ हफ्तों में काफी बैंकों ने अपने डिपॉजिट रेट बढ़ा दिए हैं। यह ट्रेंड जारी रहेगा, क्योंकि जब क्रेडिट की मांग बढ़ती है, तो ज़ाहिर है, बैंक उस क्रेडिट की मांग को तभी पूरा कर सकते हैं और उसे सपोर्ट दे सकते हैं, जब उनके पास ज्यादा

डिपॉज़िट हों। वे क्रेडिट की मांग को पूरा करने के लिए हमेशा केंद्रीय बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं रह सकते; उन्हें अपने खुद के संसाधन और फंड जुटाने होंगे। सबसे ज्यादा संभावना यही है।

चलनिधि के मामले में, जैसा कि मेरे वक्तव्य में कहा गया है, हम मौजूदा चलनिधि की स्थिति से निपटने के लिए दो-तरफ़ा परिचालन करेंगे। पिछले महीने, लगभग तीन-चार दिनों के लिए चलनिधि में अचानक कमी आ गई थी, जिसकी वजह बहुत ज्यादा जीएसटी और दूसरे कर का संग्रह था। हमने अत्यधिक संतुलित परिचालन किया। हमने तीन दिनों की परिपक्वता वाला रेपो परिचालन किया। हमारी कोशिश यह पक्का करना होगा कि चलनिधि काफ़ी मात्रा में बनी रहे। और क्रेडिट की मांग को सपोर्ट देने के लिए, बैंक शायद डिपॉज़िट रेट बढ़ाएंगे और ज्यादा डिपॉज़िट जुटाने की कोशिश करेंगे। उप गवर्नर पात्रा ने अभी-अभी बैंकों द्वारा डिपॉज़िट जुटाने का अभियान शुरू करने का उल्लेख किया था; मुझे उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

एम. गोवर्धन रंगन, इकॉनॉमिक टाइम्स:

एमपीसी के निर्णय के संदर्भ में, एमपीसी के सर्वसम्मत फैसले पर करेंसी का कितना असर पड़ा? क्योंकि एक लाइन में यह उल्लेख है कि अमरीकी डॉलर की मज़बूती का असर महंगाई पर भी पड़ सकता है।

शक्तिकांत दास:

मौद्रिक नीति एक ऐसा ढांचा है जो विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए महंगाई को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। महंगाई और विकास की गतिशीलता ही वह मुख्य कारक है जो मौद्रिक नीति के निर्णयों को तय करती है। विनिमय दर का असर परोक्ष रूप से पड़ सकता है, क्योंकि रुपये की कमज़ोरी से आयातित महंगाई बढ़ती है। महंगाई पर इसका असर निश्चित रूप से एक कारक है, लेकिन विनिमय दर अपने आप में एमपीसी के लिए विचार करने का कोई कारक नहीं है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद। अब मैं सीएनबीसी-टीवी18 की सुश्री लता वेंकटेश की ओर रुख करूँगा।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी18:

आपने इस बात को दोहराया कि मैक्रो-इकॉनॉमिक्स (समष्टि अर्थशास्त्र) के संकेतक मज़बूत हैं; आपने बताया कि विकास दर काफी अच्छी है; क्षमता उपयोग अपने दीर्घकालिक औसत से अधिक है और ज़ाहिर है, आयात की मांग भी काफी तेज़ रही है। फिर भी, यदि हम मौजूदा मुद्रास्फीति दर को देखें, तो हमारी वास्तविक ब्याज दरें काफी ज्यादा ऋणात्मक हैं। क्या आप दरों में तेज़ी से बढ़ोतरी करके (फ्रंट लोड) जल्द से जल्द वास्तविक ब्याज दरों को धनात्मक स्तर पर लाना चाहेंगे? आरबीआई 'तटस्थ दर' को किस नज़रिए से देखता है? क्या आप इसे

मुद्रास्फीति दर से 1% अधिक, या 0.75% अधिक के रूप में देखते हैं? साथ ही, यदि आप बता सकें, तो चालू खाता घाटे को लेकर आपका क्या अनुमान है?

शक्तिकांत दास:

सीएडी के अनुमान के संबंध में, हमने कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों के विभिन्न स्तरों को आधार मानकर कई तरह के परिदृश्य विश्लेषण किए हैं; और इन विश्लेषणों के आधार पर, हमें यह विश्वास है कि सीएडी एक टिकाऊ और नियंत्रित स्तर पर ही बना रहेगा। हालाँकि, मैं यहाँ कोई विशिष्ट आँकड़ा या संख्या नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ये आँकड़े भी बदलते रहते हैं। लेकिन इस समय, हमारे अनुमानों के आधार पर भी, हमें यही लगता है कि सीएडी एक प्रबंधनीय स्तर पर ही रहेगा। जहाँ तक ऋणात्मक ब्याज दरों का सवाल है, तो हाँ - ऋणात्मक ब्याज दरें निश्चित रूप से चिंता का विषय हैं; और यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एमपीसी (मौद्रिक नीति समिति) अपनी बैठकों के दौरान, और साथ ही रिज़र्व बैंक के भीतर भी आंतरिक चर्चाओं में, विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करती है।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी18:

मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या आप दरों में तेज़ी से बढ़ोतरी करके (फ्रंट लोड) जल्द से जल्द उन्हें धनात्मक स्तर पर लाना चाहेंगे?

शक्तिकांत दास:

यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं अभी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि यह भविष्य में उभरने वाली आर्थिक परिस्थितियों और समीकरणों पर निर्भर करेगा। इसके दो मुख्य पहलू हैं: पहला - हमारा प्राथमिक लक्ष्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके उसे हमारे निर्धारित लक्ष्य के करीब लाना; और दूसरा - आर्थिक विकास की संभावनाओं, तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद अनिश्चितताओं और घटनाक्रमों को भी अपने निर्णयों में समुचित स्थान देना। हम दरों में तेज़ी से बढ़ोतरी करेंगे (फ्रंट लोड), या फिर उन्हें धीरे-धीरे और क्रमिक रूप से बढ़ाएँगे - इस सटीक कार्यप्रणाली का आकलन करना मैं आप पर छोड़ता हूँ। एमपीसी, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ही, अत्यंत सोच-समझकर और संतुलित कदम उठाएगी। इसके अलावा, मेरे लिए यह बताना संभव नहीं होगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। शायद आप उस तरह के 'डॉट प्लॉट' का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे यूएस अपनाता है। लेकिन आज हम जिस अनिश्चित माहौल में जी रहे हैं, उसे देखते हुए इस 'डॉट प्लॉट' को भी हर पखवाड़े (दो हफ्ते में) बदलना पड़ेगा।

लता वैकटेश, सीएनबीसी-टीवी18:

मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि अगले साल के लिए भी आपका महंगाई का अनुमान 5 प्रतिशत है। आपने पहली तिमाही के लिए एक नया आंकड़ा दिया है, और वह अभी भी 4 प्रतिशत से एक प्रतिशत ज्यादा है, जो कि एमपीसी का लक्ष्य है। इसलिए, क्या आप पहले से ही कदम उठाएंगे?

शक्तिकांत दास:

डॉ. पात्रा, क्या आप कुछ जोड़ना चाहेंगे?

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

जब हम महामारी के दौर में थे, तो सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी - महंगाई ज्यादा थी और नीतिगत दर कम थी। अब हमारे पास दो चीज़ें बदल रही हैं - एक तो नीतिगत दर बढ़ रही है, और दूसरी तरफ़ महंगाई कम होने की संभावना है। तो, कुछ भी हो सकता है। अब दो चीज़ें बदल रही हैं। यह शायद जल्दी हो जाए या शायद देर से।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं ब्लूमबर्ग के श्री अनूप रॉय की ओर रुख करूंगा।

अनूप रॉय, ब्लूमबर्ग:

आप कह रहे थे कि चालू खाता घाटा टिकाऊ रहेगा। इससे पहले, आपने कहा था कि सीएडी मामूली है। हाल के व्यापार आंकड़ों के बाद, कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि सीएडी, जीडीपी के 4 प्रतिशत तक हो सकता है। तो, आपको किस बात से इतना भरोसा है कि सीएडी टिकाऊ और मामूली रहेगा? आपके पिछले अध्ययन में भी टिकाऊ सीएडी लगभग 2.5 प्रतिशत या उसके आस-पास था।

शक्तिकांत दास:

इस सवाल का जवाब उप गवर्नर डॉ. पात्रा को देने दीजिए।

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

पूरे साल के सीएडी का आकलन सिर्फ एक महीने के व्यापार घाटे के आधार पर नहीं किया जा सकता। आपके पास अभी सिर्फ मई और जून के आंकड़े हैं, जो ज्यादा थे। मैं आपको व्यापार घाटे के बारे में कुछ तथ्य बताता हूँ। सबसे पहले, निर्यात में जो थोड़ी-बहुत गिरावट आई है, उसकी वजह यह है कि पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात धीमा पड़ गया है। अब सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए निर्यात कर और साथ ही अप्रत्याशित कर(विंडफॉल टैक्स) में कटौती की है। और हमें उम्मीद है कि एक महीने के भीतर ही यह सब फिर से पटरी पर आ जाएगा, क्योंकि शुल्क में की गई यह कटौती काफी बड़ी है। दूसरी बात, आयात के मामले में, तेल की औसत कीमत- जिसकी घोषणा हमने एमपीसी में की थी - 105 अमरीकी \$ प्रति बैरल थी। लेकिन

आज यह 94 अमरीकी \$ प्रति बैरल पर व्यापार कर रहा है। सभी कमोडिटी की कीमतें नरम पड़ रही हैं। इसलिए, हमें आयात के मोर्चे पर काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

अब, चालू खाता घाटे के बारे में बात यह है कि इसका आकार मायने नहीं रखता। सवाल यह है कि क्या इसे फाइनेंस किया जा सकता है या नहीं? अब एफडीआई पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। पोर्टफोलियो प्रवाह बड़े पैमाने पर वापस आने लगे हैं। 1 अगस्त को हमें जुलाई महीने के कुल पोर्टफोलियो प्रवाह के बराबर राशि मिली। ट्रेड क्रेडिट मज़बूत हैं। ईसीबी के लिए, हमने इसे हासिल करने के अवसरों को बढ़ाया है, और एनआरआई जमा को भी नियमित किया जा रहा है। इसलिए, मुझे लगता है कि इसे आसानी से फाइनेंस किया जा सकता है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'द हिंदू' से श्री ललतेंदु मिश्र की ओर रुख करूँगा।

ललतेंदु मिश्र, द हिंदू:

गवर्नर साहब, अब हम एक तीसरी अप्रत्याशित घटना('ब्लैक स्वान') घटना का सामना कर रहे हैं, जो एशिया में घटित हो रही है। क्या हम इसे लेकर चिंतित हैं? यदि ऐसा होता है, तो क्या आपके पास स्थिति को संभालने के लिए कोई उपाय है?

शक्तिकांत दास:

शायद आप ताइवान में घटित हो रही घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। इसे 'ब्लैक स्वान' घटना कहना अभी बहुत जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि इसे शुरू हुए अभी केवल दो या तीन दिन ही हुए हैं। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, ताइवान के साथ हमारा व्यापार बहुत ही कम है। यह हमारे कुल व्यापार का लगभग 0.7 प्रतिशत है। इसलिए, भारत पर इसका प्रभाव बहुत ही नगण्य होगा। एफडीआई और अन्य माध्यमों से होने वाला पूँजी प्रवाह भी बहुत कम है। इसलिए, ताइवान में जो कुछ भी हो रहा है या होने की संभावना है, उसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'इन्फॉर्मिस्ट मीडिया' से श्री बिजोय इडिचेरियाह की ओर रुख करूँगा, ताकि वे अपना प्रश्न पूछ सकें।

बिजोय इडिचेरियाह, इन्फॉर्मिस्ट मीडिया:

क्या आरबीआई और एमपीसी के लिए 'डीकपलिंग' (वैश्विक रुझानों से अलग होना) पर विचार करना संभव है? क्योंकि हमने अतीत में आरबीआई के वक्तव्यों में इस शब्द का प्रयोग होते हुए सुना है। क्या वास्तव में वैश्विक समकक्षों और वैश्विक खिलाड़ियों से अलग होना संभव है, जबकि इतने सारे कारक एक साथ काम कर रहे हों? अब जब आप रेपो दर के मामले में

महामारी से पहले के स्तर से काफी ऊपर पहुँच चुके हैं, तो क्या असल में 'न्यूट्रल स्टैंड्स' (तटस्थ रुख) अपनाते पर कोई चर्चा हुई थी? और क्या जयंत वर्मा सर का इस रुख पर असहमति जताना इसी वजह से था?

शक्तिकांत दास:

असहमति की वजह वगैरह जानने के लिए, आपको अलग-अलग सदस्यों के 'मिनट्स' (बैठक के कार्यवृत्त) का इंतज़ार करना होगा। एमपीसी में अलग-अलग सदस्य क्या कहते हैं, उसे अपनी भाषा में बताना मेरे लिए सही नहीं होगा। उनके कार्यवृत्त दो हफ़्तों के बाद जारी होंगे और आप उन्हें देख पाएँगे। जहाँ तक 'डीकपलिंग' (अलग होने) की बात है, तो मुख्य बात यह है कि हम एक वैश्वीकृत दुनिया में जी रहे हैं; इसलिए, भारत पर ज़ाहिर तौर पर आस-पास हो रही घटनाओं का असर पड़ता है और आगे भी पड़ेगा। मेरे वक्तव्य में एक वाक्य है कि भारत इन सभी भू-राजनीतिक संकटों और महामारी से जुड़े झटकों से प्रभावित हुआ है। इसलिए, भारत पर इसका असर पड़ेगा।

अलग-थलग हो जाने के बारे में हमने एक खास संदर्भ में बात की थी, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम पूरी तरह से अलग-थलग हैं। हम अपने आस-पास हो रही घटनाओं से पूरी तरह से कटे हुए या अलग नहीं हैं। पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। हमने पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा भी है, और आज भी हम इसे देख रहे हैं। आज दुनिया भर में एक बात जो हो रही है, वह यह है कि व्यापार, पूंजी के प्रवाह और भू-राजनीति के मामले में दुनिया और भी ज़्यादा बँटती जा रही है। शायद अब दुनिया पहले जैसी 'सपाट' नहीं रही। इसलिए, ऐसी स्थिति में, भारत पर भी अपने आस-पास हो रही घटनाओं का असर ज़रूर पड़ेगा।

बिजॉय इडिचेरिया, इन्फॉर्मिस्ट मीडिया:

क्या 'तटस्थ रुख' अपनाते पर कोई चर्चा हुई थी? क्योंकि अब आप महामारी से पहले के दौर से काफी आगे निकल चुके हैं।

शक्तिकांत दास:

इस बारे में क्या चर्चा हुई थी, यह आपको बैठक के कार्यवृत्त में पता चल जाएगा।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'बिजनेस स्टैंडर्ड्स' के श्री सुब्रत पांडा से सवाल पूछने का आग्रह करूँगा।

सुब्रत पांडा, बिजनेस स्टैंडर्ड्स:

क्या आरबीआई को इस बात की चिंता है कि महँगाई के लगातार बने रहने के पीछे 'माँग-जनित कारक' की भी कोई भूमिका है? आपने कहा है कि महँगाई अपने चरम पर पहुँच चुकी

है; ऐसे में, आप किस स्तर पर पहुँचने के बाद अपनी नीतियों में 'विराम' देने के बारे में सोचेंगे?

शक्तिकांत दास:

जहाँ तक मौजूदा महँगाई का सवाल है, तो इसमें 'माँग-जनित कारक' की कोई खास भूमिका नहीं है। इसकी मुख्य वजहें हैं - आपूर्ति-श्रृंखला से जुड़ी विभिन्न समस्याएँ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे अलग-अलग घटनाक्रम, और 'आयातित महँगाई'। भारत ने उस तरह की भारी-भरकम चलनिधि (नकदी) या अन्य प्रकार के आर्थिक प्रोत्साहन अपनी अर्थव्यवस्था में नहीं डाले, जैसा कि कई अन्य देशों - विशेष रूप से विकसित देशों - ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दिए थे। उन देशों में इस वजह से माँग का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसने महँगाई को और भी ज़्यादा भड़का दिया। जहाँ तक भारत की बात है, तो हमारी मौद्रिक नीति से जुड़े कदमों ने महँगाई को बढ़ाने का काम नहीं किया है। हमारे विश्लेषण से फिलहाल तो यही निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। महँगाई मुख्य रूप से आपूर्ति-श्रृंखला और अंतरराष्ट्रीय कारकों की वजह से ही बढ़ रही है। जहाँ तक 'विराम' लेने की बात है, तो अभी यह कहना बहुत मुश्किल है कि हम किस स्तर पर जाकर रुकेंगे; क्योंकि मौजूदा हालात बहुत ही तेज़ी से बदल रहे हैं और उनमें अनिश्चितता भी बहुत ज़्यादा है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं मिंट से सुश्री गोपिका गोपाकुमार की ओर रुख करूँगा।

गोपिका गोपाकुमार, मिंट:

मेरा सवाल उन उपायों के संबंध में है जो आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाने के लिए पेश किए थे। इन उपायों को पेश किए हुए एक महीना हो गया है, जिनका उद्देश्य एनआरई जमा को बढ़ाना और एनआरई जमा पर दी जाने वाली छूटों को लागू करना था। इन उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है? बैंकर लगातार यह कह रहे हैं कि एनआरई जमा के लिए बहुत अधिक माँग नहीं देखी गई है; तो असल में माँग कितनी रही है? और दूसरी बात, नीति आयोग ने डिजिटल बैंकों के लिए एक नियामक ढांचा जारी किया है। क्या आरबीआई डिजिटल बैंकों की स्थापना के पक्ष में है?

शक्तिकांत दास:

हमने 6 जुलाई को पूंजी प्रवाह से संबंधित उपायों की घोषणा की थी; आज ठीक एक महीना पूरा हो गया है। यह आवश्यक था कि बैंकों के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) यह तय करें कि वे जमा पर कितना 'स्प्रेड' (ब्याज दर का अंतर) रखेंगे। कई बैंकों और उनके निदेशक मंडलों ने अपने स्वयं के निर्णय लेते हुए यह घोषणा की है कि वे इन जमाओं पर किस प्रकार की उच्च ब्याज दरें पेश करेंगे। अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी; हमें थोड़ा इंतज़ार

करना होगा और स्थिति का मूल्यांकन करना होगा। अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इन उपायों का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बैंकों ने अभी-अभी अपने निर्णय लिए हैं; शायद लगभग एक महीने बाद, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की बेहतर स्थिति में होऊंगा।

डिजिटल बैंकिंग आदि के संबंध में, संपूर्ण डिजिटल क्षेत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम पूरे डिजिटल जगत का अध्ययन कर रहे हैं - न केवल साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा आदि के दृष्टिकोण से, बल्कि वित्तीय सेवा क्षेत्र में इसकी भूमिका के संदर्भ में भी; साथ ही, हम 'डिजिटल बैंकिंग यूनिट' ढांचे पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी घोषणा हमने पिछले महीने की थी। हम इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि डिजिटल ऋण की संभावनाओं का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। वर्तमान में - और आज भी - डिजिटल ऋण देने का कार्य जारी है। आज, बैंकों द्वारा डिजिटल ऋण प्रदान किया जा रहा है। कई एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) भी हैं जो डिजिटल ऋण देने की गतिविधियों में संलग्न हैं। अतः, यह एक ऐसी गतिविधि है जो निरंतर चल रही है, और यह क्षेत्र बड़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है। इसलिए, इस संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संभालने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा, रिज़र्व बैंक उभरती हुई उन आवश्यकताओं के अनुरूप उचित कदम उठाएगा। अभी इस समय, मैं कोई पक्का जवाब नहीं दे पाऊँगा कि हम यह करेंगे या वह करेंगे; इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं रॉयटर्स की सुश्री स्वाति भाट शेट्टे की ओर रुख करूँगा।

स्वाति भाट शेट्टे, रॉयटर्स:

हाल के दिनों में, और आपके भाषणों में भी, आपने करेंसी (मुद्रा) पर आरबीआई का रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है। आपने कहा है कि आरबीआई करेंसी की रक्षा के लिए मौजूद है और बाज़ार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव नहीं होने देगा। मैं बस यह समझना चाहती थी कि आपके मन में उतार-चढ़ाव की क्या परिभाषा है, क्योंकि हमने कुछ दिनों में देखा है कि रुपया पाँच से आठ पैसे के दायरे में ही फंसा रहा, लेकिन आरबीआई बाज़ार में बहुत सक्रिय रहा। इसलिए, उस विशेष दिन इसे उतार-चढ़ाव कहना उचित नहीं होगा। और हाल के दिनों में ऐसा कई बार हुआ है। तो, उतार-चढ़ाव की आरबीआई की परिभाषा क्या है? क्या करेंसी का कोई ऐसा आंतरिक स्तर है जिसे आरबीआई अपने मन में रखता है? हमने देखा कि जब यह 80 के स्तर पर पहुँचा तो बहुत अधिक हस्तक्षेप हुआ, और हमने लगातार देखा है कि आरबीआई इसे उस स्तर से नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तो, इस पर आपके क्या विचार हैं?

शक्तिकांत दास:

क्रिकेट की शब्दावली का उपयोग करते हुए, उतार-चढ़ाव का मूल अर्थ गेंद के 'स्विंग' (उछाल) का स्तर और उसकी तीव्रता होगी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उप गवर्नर डॉ. माइकल डी. पात्रा को देने दें।

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

गवर्नर ने कई बार कहा है कि हमारे मन में कोई निश्चित स्तर नहीं है। उतार-चढ़ाव को आमतौर पर 'विचरण' के किसी माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परिभाषा के अनुसार, 'माध्य' से विचलन होता है। हम माध्य से विचलन पर नज़र रखते हैं और उसी के अनुसार अपनी कार्रवाई तय करते हैं।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं निक्केई के श्री रयोसुके हानाडा की ओर रुख करूँगा।

रयोसुके हानाडा, निक्केई:

मैं पड़ोसी देश में चल रहे आर्थिक संकट के बारे में पूछना चाहूँगा। इस समय, क्या रिज़र्व बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच किसी और सहायता के संबंध में कोई चर्चा चल रही है, जैसे कि 'करेंसी स्वैप समझौता' या कोई अन्य उपाय?

शक्तिकांत दास:

एक केंद्रीय बैंक के तौर पर, हम अपने पड़ोसी देशों या किसी भी दूसरे देश में हो रहे आर्थिक घटनाक्रमों पर कोई टिप्पणी नहीं करते। हम उन्हें इस नज़रिए से ज़रूर देखते हैं कि उनका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। श्रीलंकाई सरकार के साथ होने वाली चर्चाओं के संबंध में, यह हमेशा सरकार-से-सरकार के बीच होने वाली चर्चा होती है। रिज़र्व बैंक, श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की सीधी चर्चा में शामिल नहीं है। इस तरह की चर्चाएँ हमेशा सरकारी स्तर पर ही होती हैं।

योगेश दयाल:

अब मैं पीटीआई से श्री आशीष अगाशे की ओर रुख करूँगा।

आशीष अगाशे, पीटीआई:

यह आज बीबीपीएस की घोषणा के बारे में था; यह कैसे काम करेगा?

दूसरी बात, इसके पीछे मकसद क्या है? क्या इसका मकसद बैंकों के मार्जिन को कम करना है, जिस पर आरबीआई ने पहले भी चिंता जताई थी? या फिर यह रेमिटेंस (धन प्रेषण) के प्रवाह को बढ़ाने जैसा कोई कदम है?

शक्तिकांत दास:

में उप गवर्नर रबी शंकर से अनुरोध करूंगा कि वे इस सवाल का जवाब दें।

टी. रबी शंकर:

जब यह व्यवस्था शुरू की गई थी, तब निश्चित रूप से मार्जिन का मुद्दा हमारे दिमाग में नहीं था। यह मुख्य रूप से एनआरआई और उनके यहाँ रहने वाले रिश्तेदारों की सुविधा के लिए उठाया गया कदम था। इसके कुछ फायदे हैं। पहला यह कि हो सकता है किसी एनआरआई के पास बिल जमा करने वाली सभी सेवाओं (बिल कलेक्टर्स) तक पहुँच न हो, जबकि इस सिस्टम पर 20,000 से भी ज़्यादा विकल्प उपलब्ध हैं। अब ये सभी विकल्प उनके लिए उपलब्ध हो जाएँगे। हो सकता है कि सभी एनआरआई के भारत में एनआरआई खाते न हों। इसलिए, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो, इसका पूरा विचार यह है कि वे किसी भी तरह का बिल - चाहे वह बीमा, बिजली, यूटिलिटी, या कोई अन्य बिल हो - उस इंटरफ़ेस के ज़रिए जमा कर पाएँगे जो एक्सचेंज हाउस या बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मुख्य जोर सुविधा पर है, न कि मार्जिन या ऐसी किसी अन्य चीज़ पर।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं ईटी नाउ से श्री अंकुर मिश्र की ओर रुख करूंगा।

अंकुर मिश्र, ईटी नाउ:

में एक बार फिर आपका ध्यान 'रुख' वाले पहलू पर दिलाना चाहूँगा। चूँकि रेपो दर महामारी से पहले के स्तर को पार कर चुकी है, तो मैं बस यह जानना चाहता था कि क्या यह उम्मीद करना सही होगा कि इस साल, हमारा रुख 'निभावकारी रुख हटा लेना' से बदलकर 'तटस्थ' हो जाएगा?

शक्तिकांत दास:

नीति के संबंध में भविष्य का कोई मार्गदर्शन देना संभव नहीं होगा। जब हम दरों में कटौती के दौर में होते हैं, तो भविष्य का मार्गदर्शन देना आसान होता है। लेकिन जब हम दरों में बढ़ोतरी के दौर में होते हैं - और मौजूदा अनिश्चितता के स्तर को देखते हुए - तो मैं दरों से जुड़े कदमों के बारे में भविष्य का कोई मार्गदर्शन देने का जोखिम नहीं उठाऊँगा। भविष्य के लिए जो मार्गदर्शन दिया गया है, वह मूल रूप से 'अकोमोडेशन' (निभाव) को वापस लेना है, और हम महंगाई को नियंत्रित करना चाहते हैं। इससे जुड़े अपने निष्कर्ष आपको स्वयं निकालने होंगे।

अंकुर मिश्र, ईटी नाउ:

दूसरा, सिर्फ एक ही बैंक है जो काफी समय से पीसीए में बना हुआ है। वह बैंक पिछले लगभग सात-आठ तिमाहियों से यह दावा कर रहा है कि वह पीसीए के उन पैमानों से बाहर आ गया है। किसी एक खास संस्था से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के तौर पर, उस संस्था को पीसीए से बाहर निकालने के लिए आपके क्या विचार हैं?

शक्तिकांत दास:

मुझे लगता है कि उप गवर्नर श्री एम. के. जैन शायद इस सवाल का जवाब दे सकते हैं।

एम. के. जैन:

हमें वह अनुरोध मिला है। हम उसकी जाँच कर रहे हैं। हम कोई भी फ़ैसला लेने से पहले सिर्फ मात्रात्मक पैमानों को ही नहीं, बल्कि गुणात्मक पैमानों को भी जाँचते हैं, क्योंकि जब किसी बैंक को पीसीए से बाहर निकाला जाता है, तो वह एक टिकाऊ आधार पर होना चाहिए।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं बिजनेस टुडे से श्री आनंद अधिकारी की ओर रुख करूँगा।

आनंद अधिकारी, बिजनेस टुडे:

बैंक जमा का कितना प्रतिशत बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है? क्योंकि मैं भारत औसत उधार और जमा दरों के लिए आरबीआई के कुछ डेटा देख रहा था। जहाँ उधार दरें 14 आधार अंक बढ़ी हैं, वहीं जमा दरें 4 या 5 आधार अंक बढ़ी हैं। मैं बस यह समझना चाहता हूँ कि आज बैंक जमा का कितना प्रतिशत बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है?

शक्तिकांत दास:

बैंक जमा बाहरी बेंचमार्क से नहीं जुड़े होते; यह बैंक की उधार दरें होती हैं जो बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी होती हैं।

आनंद अधिकारी, बिजनेस टुडे:

एसबीआई और कुछ अन्य बैंकों जैसे कुछ बैंक थोक जमा की सुविधा देते हैं जो बाहरी बेंचमार्क से जुड़े होते हैं; यहाँ तक कि यस बैंक ने भी हाल ही में एक ऐसा उत्पाद पेश किया है जो बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है।

शक्तिकांत दास:

जमा दरें और इसलिए ब्याज दरें पूरी तरह से अविनियमित हैं। इसलिए, यह अलग-अलग बैंकों पर निर्भर करता है कि वे अपने डिपॉजिट दरें खुद तय करें। लेकिन जहाँ तक आरबीआई की बात है, बाहरी बेंचमार्क जमा दर पर लागू नहीं होता है।

आनंद अधिकारी, बिजनेस टुडे:

आज की तारीख तक हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे यह पता चल सके कि कितने प्रतिशत जमा बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी हुई हैं। मेरा मतलब है, क्या ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है?

शक्तिकांत दास:

हम वह डेटा नहीं रखते क्योंकि हमारा बाहरी बेंचमार्क जमा दर से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए, हमारे द्वारा उस डेटा को रखने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कुछ बैंक इसे तिजोरी-बिल या 1 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति, 2 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति या 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति जैसे बाहरी बेंचमार्क से जोड़ रहे हैं, तो यह उनका अपना फैसला होगा।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं जी बिजनेस से श्री अनुराग शाह की ओर रुख करूँगा।

अनुराग शाह, जी बिजनेस:

साख निर्धारण एजेंसी के विनियमन को लेकर आरबीआई को क्या दिक्कतें हैं? अभी उनका विनियामक कोई और है, लेकिन उस विनियामक के ज़रिए ऋण की रेटिंग की जा रही है।

शक्तिकांत दास:

आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ बैलेंस शीट देखते हैं, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग देती है, और उसका बैंकों पर क्या असर पड़ता है, हम सिर्फ उसी हिस्से से जुड़े मामलों को देखते हैं। उप गवर्नर राजेश्वर राव, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस सवाल का जवाब दें।

एम. राजेश्वर राव:

हमें कोई दिक्कत नहीं है; रेटिंग एजेंसियों को सेबी विनियमित करता है, लेकिन बैंकों को कोई रियायती जोखिम दर वगैरह देने के लिए बैंक ऋण की रेटिंग ज़रूरी होती है। इसलिए, उन दिशानिर्देशों को आरबीआई को ही बनाना होता है, और वे गाइडलाइंस बना दी गई हैं, जिनका पालन रेटिंग एजेंसियों से करने की उम्मीद की जाती है।

अनुराग शाह, जी बिजनेस:

अपनी पिछली पॉलिसी में आपने उल्लेख किया था कि डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी गाइडलाइंस जल्द ही आ जाएँगी, तो फिर इसमें देरी क्यों हो रही है? क्या इस मामले को लेकर नज़रिया बदल गया है? क्या इसका दायरा इतना बड़ा हो गया है? और क्या इसी वजह से इसमें देरी हो रही है? इसके साथ ही, हम यह भी देख रहे हैं कि बैंकिंग धोखाधड़ी के कारण लोगों की बहुत सारी शिकायतें सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि वे कई तरह की धोखाधड़ी का

शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस भी कई मामलों में उनकी मदद नहीं कर पा रही है।

शक्तिकांत दास:

ज्यादातर जो धोखाधड़ी हो रही है, वह उन संस्थाओं द्वारा की जा रही है जो विनियमित नहीं हैं। वे आरबीआई के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे आरबीआई के लाइसेंस के बिना काम करती हैं, और वे यह सब अपनी मर्जी से करती हैं। इसलिए, इसे रोकने की जिम्मेदारी कानून लागू करने वाली एजेंसी या कानून लागू करने वाले अधिकारियों की है। आरबीआई में हम केवल उन्हीं संस्थाओं को रेगुलेट कर सकते हैं जो हमारे साथ पंजीकृत हैं, जिन्हें हमने लाइसेंस/अनुमति दी है। लेकिन हम अभियान और विज्ञापनों के ज़रिए जागरूकता ज़रूर फैलाते हैं। डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के बारे में एक और बात, हाल ही में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि इसमें ज्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि हम इसका बहुत ध्यान से अध्ययन करना चाहते थे। यह जल्द ही आ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हम मौद्रिक नीति में थोड़े व्यस्त थे, इसलिए आपको यह जल्द ही मिल जाएगा।

योगेश दयाल:

धन्यवाद। अब मैं मनी कंट्रोल की सुश्री सिद्धि नायक से सवाल पूछने के लिए रुक करूंगा।

सिद्धि नायक, मनीकंट्रोल:

मैं यह जानना चाहती थी कि क्या रिज़र्व बैंक की चलनिधि की स्थिति को सामान्य करने की कई सालों से चल रही प्रक्रिया इसी वित्त वर्ष में पूरी हो सकती है, क्योंकि चलनिधि तेज़ी से कम हो रही है - यह तो पहला सवाल है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान के जो उपाय आपने अभी घोषित किए हैं, क्या आरबीआई को इस संबंध में वास्ट्रो खाते खोलने के लिए कोई अनुरोध मिला है?

शक्तिकांत दास:

सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब उप गवर्नर रबी शंकर देंगे। सवाल का पहला हिस्सा यह है कि क्या लिक्विडिटी को सामान्य करने की प्रक्रिया मौजूदा साल में पूरी हो जाएगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर चलनिधि आज भी काफी ज्यादा है। यह लगभग पाँच से छह लाख करोड़ है। अगर आप स्टैंडिंग डिपॉज़िट फ़ैसिलिटी को भी इसमें जोड़ लें - यानी वह पैसा जो हर दिन के आखिर में एसडीएफ के तहत हमारे पास आता है - साथ ही 14-दिन के वीआरआरआर और 28-दिन के वीआरआरआर के तहत जमा पैसा, और सरकार का संभावित खर्च - अगर आप इन सबको एक साथ जोड़ें, तो सिस्टम में लिक्विडिटी पाँच लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जो लगभग छह लाख करोड़ तक पहुँच रही है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, यह एक बहु-वर्षीय चक्र होगा। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुछ

टीएलटीआरओ, जिनकी घोषणा हमने महामारी के पहले वर्ष में 3 साल के लिए की थी, उनमें से कुछ 2023 में ही परिपक्व होंगे और यह प्रक्रिया अगले वर्ष भी जारी रहेगी।

टी. रबी शंकर:

हाँ, हमें बैंकों से व्यापार के लिए रुपये में सेटलमेंट मैकेनिज्म के लिए वास्ट्रो खाता के संबंध में कुछ अनुरोध मिले हैं। कई बड़े बैंक अभी भी अपनी अंदरूनी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। विदेशी मुद्रा में हमारी टीम के साथ काफी चर्चाएँ चल रही हैं। इसलिए, आने वाले दिनों में हमें और भी अनुरोध मिलने लगेंगे। लेकिन हमें कुछ प्रस्ताव मिल चुके हैं।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लगभग अंत पर पहुँच चुके हैं। आपकी अनुमति से, मैं आखिरी दो सवाल लूँगा। मैं बीक्यू प्राइम के श्री विश्वनाथ नायर को अपना सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

विश्वनाथ नायर, बीक्यू प्राइम:

स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स के लिए आपने जिन उपायों की घोषणा की है, मैं बस यह समझना चाहता था कि आरबीआई इन उपायों के ज़रिए असल में क्या हासिल करना चाहता है। दूसरा हिस्सा बीबीपीएस से जुड़े सवाल के बारे में है: क्या सिर्फ़ एक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के अलावा, यह वास्तव में इनवर्ड क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स (विदेश से आने वाले भुगतानों) के संबंध में कोई बड़ी समस्या हल करेगा?

शक्तिकांत दास:

जैसा कि उप गवर्नर ने समझाया, यह एक सुविधा है जो हमने दी है। इसका उद्देश्य असल में ज़्यादा इनवर्ड रेमिटेंस (विदेश से आने वाले पैसे) को बढ़ावा देना या ऐसा कुछ नहीं है; यह बस एक सुविधा है जो हम उपलब्ध करा रहे हैं। इससे कई परिवारों, खासकर बुजुर्ग नागरिकों के लिए भुगतान करना आसान हो जाएगा - जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं और जिन्हें भुगतान करने में दिक्कत हो सकती है, चाहे वह ऑनलाइन भुगतान हो (क्योंकि वे इससे परिचित नहीं हैं) या कुछ स्थितियों में भुगतान करने के लिए उन्हें कहीं जाना पड़ता हो। यह बस एक सुविधा है जो हमने भुगतान करने में आसानी लाने के लिए दी है, और बस इतना ही। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स के बारे में पूछी थी; उस सवाल का जवाब रबी शंकर दे सकते हैं।

टी. रबी शंकर:

मूल विचार यह है कि स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को वित्तीय बाज़ार में 'बाज़ार निर्धारक (मार्केट मेकर्स) के तौर पर विकसित किया जाए। अभी वे ब्याज दर बाज़ार में काफी सक्रिय हैं, लेकिन जैसा कि आप समझते होंगे, ब्याज दर और विनिमय दर बाज़ार आपस में बहुत निकट से जुड़े

होते हैं। इसलिए, उन्हें बाज़ार निर्धारक मेकर्स के तौर पर एक्सेस देने से वे अपने ग्राहकों या दूसरों को मार्केट-मेकिंग उत्पादों की पूरी श्रृंखला उपलब्ध करा पाएंगे। बाज़ार उपयोक्ताओं के नज़रिए से देखें तो, कीमत-निर्धारण के मामले में बाज़ार-निर्धारक के ज़्यादा विकल्प होना हमेशा एक बेहतर ऑप्शन होता है। हमें उम्मीद है कि इससे कीमत-निर्धारण की क्षमता में सुधार होगा, और यही इसका मुख्य विचार है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'द हिंदू बिजनेसलाइन' से श्री के. राम कुमार की ओर रुख करूंगा।

के. राम कुमार, द हिंदू बिजनेसलाइन:

मैं बस यह समझना चाहता था कि बैंक, अपने एनपीए(नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) कम करने की प्रक्रिया के तहत, जितने ऋण वसूल या अपग्रेड कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोन 'राइट ऑफ' (बट्टे खाते में डालना) रहे हैं। तो, क्या यह रिज़र्व बैंक के लिए चिंता का विषय है, और क्या आप इस पर ध्यान दे रहे हैं?

शक्तिकांत दास:

उप गवर्नर, श्री जैन इस सवाल का जवाब दे सकते हैं।

एम. के. जैन:

सबसे पहले, मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि ये तकनीकी और विवेकपूर्ण 'राइट ऑफ' हैं, जिनमें वसूली के अधिकार को छोड़ा नहीं जाता है। दूसरा, इन सभी ऋणों के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है, इसलिए यह बैलेंस शीट में विवेकपूर्णता को दर्शाता है और बैलेंस शीट की बेहतर स्थिति को दिखाता है। और तीसरा, पिछले ढाई सालों में हमने यह देखा है कि जहां तक 'राइट ऑफ' का सवाल है, उसमें गिरावट का रुझान है। वहीं, ऋणों के 'अपग्रेडेशन' में बढ़ोतरी का रुझान देखने को मिला है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर; और आखिरी सवाल दूरदर्शन की सुश्री श्यामा मिश्रा से है।

श्यामा मिश्रा, दूरदर्शन:

चूंकि यह आखिरी सवाल है, इसलिए हम थोड़ी और स्पष्टता चाहेंगे। रेट में बढ़ोतरी महंगाई को काबू करने के लिए की जाती है। क्या आपने इस उपाय के असर दिखने के लिए कोई समय-सीमा तय की है - कम से कम महंगाई को कुछ हद तक कम करने के लिए?

शक्तिकांत दास:

आमतौर पर, दर में बढ़ोतरी का पूरा असर दिखने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। इनका असर शुरू से ही दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन पूरा असर होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। हमने अप्रैल से जो दर संबंधी कदम उठाए हैं - जब हमने एसडीएफ को ज़्यादा दर पर (रिवर्स रेपो से 40 आधार अंक ज़्यादा) पेश किया था - और फिर मई और जून में भी - उनके पूरे असर का आकलन करने के लिए हमें शायद अक्टूबर या नवंबर तक इंतज़ार करना होगा।

लता वैकटेश, सीएनबीसी-टीवी 18:

क्या आरबीआई को लगता है कि वे न्यूट्रल रेट (तटस्थ दर) के करीब हैं या उस पर पहुँच गए हैं?

शक्तिकांत दास:

मैं रिज़र्व बैंक की सोच का खुलासा नहीं कर सकता। न्यूट्रल रेट वगैरह पर कुछ बुलेटिन लेख छपे हैं, लेकिन मैं आरबीआई की सोच का खुलासा नहीं कर सकता। आरबीआई के भीतर कई तरह की सोच और विचार होते हैं, और आखिर में वे सभी मेरे पास आते हैं। वहाँ से, सीनियर मैनेजमेंट के साथ चर्चा के बाद, आरबीआई की सोच सामने आती है। इसलिए, मेरे लिए आपके सवाल का बहुत साफ़ शब्दों में जवाब देना मुमकिन नहीं होगा। डॉ. पात्रा कुछ जोड़ना चाहते हैं।

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

तटस्थ दर (न्यूट्रल रेट) तक पहुँचने का रास्ता दो पड़ावों वाली यात्रा है। पहला पड़ाव तब आता है जब महंगाई स्वीकार्य सीमा (टॉलरेंस बैंड) के अंदर आ जाती है, और दूसरा तब जब यह लक्ष्य के साथ मेल खाने लगती है।

एम. गोवर्धन रंगन, इकॉनॉमिक टाइम्स:

एमपीसी से जुड़ा एक अलग सवाल। रिज़र्व बैंक के फैसलों से जुड़े कई रहस्यों में से एक रहस्य बैंक सीईओ के पद की मंजूरी या नामंजूरी भी रही है। तो, पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहाँ बोर्ड ने 3 साल के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन आरबीआई ने उसे घटाकर 1 साल कर दिया। इन फैसलों के पीछे क्या वजह होती है? क्योंकि सवाल यह उठता है कि अगर कोई व्यक्ति 3 साल के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह 1 साल के लिए भी उपयुक्त नहीं हो सकता; तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इन फैसलों को प्रभावित करती है?

शक्तिकांत दास:

आप किसी खास मामले का उल्लेख कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि अलग-अलग बैंकों से जुड़े खास मामलों पर मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। यह रिज़र्व बैंक का एक समग्र मूल्यांकन होता है। इसलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग बैंकों से जुड़े सवालों के जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। धन्यवाद।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। इसी के साथ, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समापन पर पहुँचते हैं। मैं अपने सभी मीडिया साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज यहाँ उपस्थित हुए। गवर्नर, उप गवर्नर्स और मेरे वरिष्ठ साथियों का भी धन्यवाद, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। तो, अगली बार तक के लिए, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

शक्तिकांत दास:

आप सभी का धन्यवाद।